

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन से “लोकल टू ग्लोबल” हो रहे स्थानीय उत्पाद “एक जिला एक उत्पादन नीति” से राजस्थान के उत्पाद विश्व पटल पर बना रहे अपनी विशिष्ट पहचान

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार “एक जिला एक उत्पाद नीति-2024” के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर लाने का प्रयास कर रही है। इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में उत्पाद का चयन किया गया है, जिससे स्थानीय संसाधनों और कौशल का बेहतर उपयोग हो सके। साथ ही, प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखते हुए प्रमुख उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के माध्यम से गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है तथा उद्यमियों को तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता



और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नीति के अंतर्गत उद्योगों को मार्जिन मनी अनुदान, एडवॉस टेक्नोलोजी और सॉफ्टवेयर खरीदने, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने

■ **उद्यमिता को मिल रहा बढ़ावा, गांवों में रोजगार के नए अवसर : भजनलाल शर्मा**

पर पुनर्भरण सहायता प्राप्त होगी। राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में इस नीति के तहत नए लघु एवं सूक्ष्म ओडीओपी उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख रुपये) तक मार्जिन मनी सब्सिडी देय है। साथ ही,

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के तकनीकी उन्नयन के लिए नवीनतम तकनीक एवं सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 5 लाख रुपये) की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। एक जिला–एक उत्पाद नीति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर किए गए खर्चों के लिए 3 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत पुनर्भरण का प्रावधान है। साथ ही, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए दो साल तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक 75 प्रतिशत पुनर्भरण भी देय है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त

राष्ट्रीय संस्थानों से एडवॉन्स टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर खरीद पर 5 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इस नीति के तहत उद्यमियों को कैंटलागिंग सेवाओं और ई–कॉमर्स वेबसाइटों के डवलपमेंट के लिए 60 प्रतिशत और अधिकतम 75 हजार तक सहायता देकर डिजिटल मार्केट के विस्तार में सहयोग दिया जा रहा है। जिससे उत्पादों की ब्रांडिंग हो सके, साथ ही, बाजार तक बहुत सुनिश्चित हो। वित्तीय प्रोत्साहन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और मार्केट विस्तार जैसे पहलों के माध्यम से यह नीति जिला स्तर के उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।

डीओआईटी के विशेष सचिव और राजस्थान हैल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

जयपुर । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने आदेश की पालना नहीं करने पर डीओआईटी के विशेष सचिव व आयुक्त हिमांशु गुप्ता व राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ हरजीवम अटल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 16 अप्रैल को तलब किया है।

आयोग ने पुलिस कमिश्नरेट को कहा है कि वे वारंट की तामील कराए। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा

ने यह आदेश सोनिका राघव के अवमानना प्रार्थना पत्र पर दिया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता ओमेन्द्र सिंह ने बताया कि उपभोक्ता आयोग ने 28 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर परिवादी के चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन 850 रुपए कटने के बावजूद उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के सेवादोष मामले में विपक्षीय पर 36 हजार रुपए का हर्जाना लगाया था। इसके बावजूद

विपक्षी अफसरों ने उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। जिसे परिवादिया ने अवमानना प्रार्थना पत्र के जरिए चुनौती देते हुए आदेश की पालना का आग्रह किया। जिस पर आयोग ने अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

गौरतलब है कि परिवादी ने साल 2021 में चिरंजीवी योजना के लिए ऑनलाइन 850 रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन योजना में उसका रजिस्ट्रेशन

नहीं हुआ। उसने दोबारा ट्रांजेक्शन किया तो रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उसे परिवादी ने दो साल में काटे गए 850 रुपए 7 दिन की अवधि में ट्रांसफर नहीं किए गए। इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देने के दौरान मार्च 2022 में 850 रुपए उसे लौटा दिए गए। उपभोक्ता आयोग ने विपक्षीगण के रकम लौटाने में देरी होने को सेवादोष करार देते हुए 36 हजार रुपए का हर्जाना लगाया, लेकिन इस आदेश की पालना नहीं की गई।

विदेश जाने पर रोक, बेटी के नाम 10 लाख रुपए की एफडीआर बनाने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में महिला के सास-ससुर और देवर को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए कहा है कि वे बिना अनुमति विदेश नहीं जाएंगे।

इसके साथ ही अदालत ने बेटी के नाम दस लाख रुपए की एफडीआर बनाने का आदेश देते हुए पक्षकारों को समझौते के लिए मध्यस्थ के समक्ष जाने को कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश सास-ससुर व देवर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते

हुए दिए।सुनवाई के दौरान ससुराल पक्ष ने अदालत को आश्चर्य किया कि वे पीडिता और उसकी बेटी के भरण पोषण के लिए हर माह 30 हजार रुपए अदा करेंगे।

इस पर अदालत ने कहा कि हर माह की 2 तारीख को पीडिता के बैंक खाते में यह राशि जमा कराई जाए। गौरतलब है कि पीडिता ने खैरख्त-तिजारा के महिला थाने में शिकायत दी थी। जिसमें कहा की उसकी शादी जनवरी, 2022 को हुई थी और उसके दो साल को

युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की

जयपुर । रामनगरिया थाना क्षेत्र में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी के लगातार दूरी बनाने से परेशान होकर युवक ने अपनी शादी की सालगिरह के अगले दिन यह कदम उठाया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट और मोबाइल में सुसाइड वीडियो भी मिला है।

पुलिस के अनुसार दौसा के बसवा निवासी शाहबाज खान (27) ने 28 फरवरी को जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। वह रेवाड़ी-मानसेर में एक निजी कंपनी में कार्यरत था। 27 फरवरी 2023 को उसकी शादी दौसा निवासी कशिश (25) से हुई थी। दंपती की दो वर्षीय बेटी भी है।

परिजनों के अनुसार, शादी के बाद से ही पत्नी कशिश अक्सर विवाद कर पीहर चली जाती थी और वापस आने से इनकार करती थी। आरोप है कि वह अपनी मर्जी से घूमने-फिरने जाती और पैसों की मांग करती थी, जिसे शाहबाज से करीब डेढ़ लाख रुपए खर्च करवाए गए। इसके बाद भी ससुराल पक्ष द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। पत्नी के कहने पर शाहबाज ने रेवाड़ी की नौकरी छोड़ दी और फरवरी 2026 में जयपुर के थांकरोटा क्षेत्र के जवसिंहपुरा में किराए

■ **सुसाइड नोट व वीडियो के आधार पर पत्नी व ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज**

का मकान लेकर नई नौकरी शुरू की, लेकिन इसके बावजूद पत्नी साथ नहीं आई। 27 फरवरी 2026 को शादी की तीसरी सालगिरह पर भी पत्नी ने कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। परेशान होकर शाहबाज ने उसे लगातार मैसेज कर बात करने की गुहार लगाई। अगले दिन 28 फरवरी की सुबह वह बाइक लेकर घर से निकला और जगतपुरा रेलवे स्टेशन की पार्किंग में बाइक खड़ी कर सीबीआई फाटक के पास ट्रेन के आगे कूद गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

कमरे की तलाशी में सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने लिखा- मेरी जिंदगी के कुछ पल मेरी बेटी फातिका को बता देना। मोबाइल में पत्नी को भेजे गए कई संदेश और रते हुए बनाया गया वीडियो भी मिला है, जिसमें वह ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाता दिख रहा है। पुलिस ने मुक्त के भाई की रिपोर्ट पर पत्नी कशिश, सास तसलीम, साले बिलाल, शाहदाब उर्फ राहुल और जिसान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

15वें वित्त आयोग से बीते चार माह में राजस्थान को 2700 करोड़ रुपये मिले

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत प्रदेश को अधिक से अधिक राशि जारी किए जाने के लिए विशेष प्रयास किए। जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं पीएम अ भीम (प्रधानमंत्री आलुपमान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन) के तहत रिकॉर्ड राशि राज्य को जारी की गई है। 15वें वित्त आयोग के तहत राजस्थान को विगत 5 वर्ष में करीब 4300 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से लगभग 2700 करोड़ की राशि विगत 4 माह में मुख्यमंत्री के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप जारी हुई है।

जे.डी.ए. में पदोन्नत हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं मिली नई पोस्टिंग

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण में पदोन्नत हुए एडिशनल चीफ इंजीनियर्स (अतिरिक्त मुख्य अभियंता) को उनके नए पदभार के साथ पोस्टिंग दी गई है। इनके कार्यभार में भी बदलाव किया गया है। पदोन्नत होने के बाद जेडीए में 11 एडिशनल चीफ इंजीनियर्स हो गए हैं। आदेश के अनुसार मोहन लाल मीणा को जोन 21 व 22, राजीव आवास योजना (बीएसयूपी-अफोर्डेबल), ईजीनियरिंग शाखाओं से समन्वय, एपेक्स एलीवेटेड प्रोजेक्ट, तकनीकी सहायक निदेशक इंजीनियरिंग प्रथम का जिम्मा सौंपा गया है। हरीशंकर मीणा को जोन 15 व 16 लोकायुक्त, एमपी, एमएलए फंड, रिंग रोड उत्तर का चार्ज दिया गया है। संजय पुनिया को जोन 11 व 12, एमएस-पीडब्ल्यू, बिजली, सिविल लाइन आरओबी को जिम्मेदारी दी गई है। राम प्रसाद रैगर को जोन 10

व 13 विधानसभा ओफसी यूटिलिटी, गुणवत्ता प्रकोष्ठ, तकनीकी सहायक डायरेक्टर थर्ड का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही नए पदोन्नत अतिरिक्त मुख्य अभियंता मोहित चौधरी को जोन ए-बी, ट्रेफिक कंट्रोल बोर्ड, रिड्डी-सिड्डी एलीवेटेड रोड का काम सौंपा गया है। विवेक शर्मा को जोन 17, 18, 19 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मुख्यालय, पीएमआईएस, सोडाला प्रोजेक्ट फाइनलिजेशन की जिम्मेदारी दी गई है। राजेन्द्र शर्मा को जोन 9 व 14, सालिगरामपुरा आरओबी, इंडूनी फाटक प्रोजेक्ट का चार्ज दिया गया है। योगेश स्वरूप माथुर को जोन 7 पीआरएन, सीएमआईएस, बजट योजना, जनसुनवाई केन्द्र सांगानेर व ड्रव्यवती प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। महेश गोयल को जोन सी-8, सांगानेर एलीवेटेड रोड,तकनीकी सहायक डायरेक्टर इंजीनियरिंग थर्ड का काम सौंपा गया है।



सांगानेर सदर पुलिस ने रिंग रोड परियोजना क्षेत्र स्थित एक डॉक्टर के घर हुई 50 लाख रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए घर के ही नौकर और नौकरानी को गिरफ्तार किया।

परिस्थितियों में घर के पालतू कुत्ते की मौत हो गई। इसके बाद जब किचन में चोरी का प्रयास हुआ। जबकि 25 फरवरी को सीसीटीवी कैमरों की सर्विसिंग हुई। इसी दौरान घर के कर्मचारी सुमित खेतान और सीमा सैनी को कैमरों की पूरी जानकारी हो गई। गत 19 मार्च की रात संदिग्ध

स्वीकार करने के बाद सुमित खेतान (38) और सीमा सैनी (34) को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से 33 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए हैं। शेष राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।

जांच में सामने आया कि जब परिवादी रकम छिपा रहे थे। तब सुमित

वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन रवाना

जयपुर (कासं)। देवस्थान की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2025-26 के तहत मंगलवार को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम-मदुरई के लिए विशेष ट्रेन को देवस्थान में जोरवार कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा-2025-26 की यह अंतिम ट्रेन थी। इसमें जयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग के कुल 990 वरिष्ठजन रामेश्वरम-मदुरई के लिए रवाना हुए हैं। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से 400 यात्री, जबकि सवाईमाधोपुर से 120 व कोटा रेलवे स्टेशन से 470 यात्री सवार हुए हैं। यह ट्रेन दो अप्रेल को रामेश्वरम पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव रामेश्वरम में एक दिन का होगा। यहां पर सभी श्रद्धालुओं को हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण चार धाम में से एक व देश के मुख्य रामनाथ स्वामी मंदिर व ज्योतिर्लिंग व मणी दर्शन करवाए जाएंगे।

देवनानी ने केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट की

तारागढ़ किला और वरुण सागर को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय सहायता दिलाने का आग्रह

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने नई दिल्ली प्रवास में मंगलवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भेंट की और अजमेर के पर्यटन विकास कार्यो और कतिपय अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भेंट में विधानसभाध्यक्ष देवनानी ने अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ किला और वरुण सागर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा की और इसके लिए यथोचित केन्द्रीय सहयोग प्रदान कराने का आग्रह किया ।

देवनानी ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़े ऐतिहासिक तारागढ़ किला के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने भी अपने बजट में वित्तीय प्रावधान की घोषणा की है। ऐतिहासिक तारागढ़ किला को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की महती आवश्यकता है। इसी प्रकार अजमेर के वरुणसागर जिसका पूर्व में नाम फाय सागर था, को भी पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है तथा यहाँ शीघ्र वरुण देवता की अष्ट धातु की एक मूर्ति भी स्थापित की जायेगी। देवनानी ने बताया कि अजमेर में अंग्रेजी और औपनिवेशिक काल की गुलामी के प्रतीक कई नामों को बदला गया है। इसी क्रम में फाय सागर का नाम भी परिवर्तित कर जल के देवता वरुण सागर के नाम पर रखा गया है । उन्होंने बताया कि वरुण सागर को एक



राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की।

■ **अजमेर में डाकघर और बीएसएनएल से सटी सड़क सम्बन्धी विषय पर कार्यवाही करने का अनुरोध**

आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने के प्रयास किए जा रहें है ।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभाध्यक्ष देवनानी का आश्चर्य किया कि ऐतिहासिक तारागढ़ किला और वरुण सागर सहित अजमेर के अन्य पर्यटन स्थलों के विकास का विस्तृत प्रोजेक्ट बनवा कर केन्द्र सरकार से समुचित केन्द्रीय सहायता दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा ।विधानसभाध्यक्ष देवनानी ने केन्द्रीय संचार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अजमेर में बीएसएनएल और डॉक घर कार्यालय के पास की सड़क को चौड़ी करने सम्बन्धी विषय पर चर्चा की तथा बताया कि अजमेर में जाम की

समस्या को दूर करने तथा सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यालय के पास की सड़क को चौड़ी करना आवश्यक है ।जनहित में इन कार्यालयों की भूमि को आवश्यकता है। क्योंकि नए एलिवेटेड रोड और आगरा फोर्ट गेट के पास प्रायः दुर्घटनाए होती है । उन्होंने सिंधिया से इस लम्बित विषय का शीघ्र निराकरण करने के लिए सर्वोच्चत अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। केन्द्रीय संचार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभाध्यक्ष देवनानी को आश्चर्य किया कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। इस अवसर पर विधानसभाध्यक्ष देवनानी ने दोनों केन्द्रीय मन्त्रियों को विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष-नवाचारों के 2 वर्ष और विधान सभा की दैनंदिनी के साथ ही अपनी स्वलिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक भेंट की।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1 1 हजार रुपए हर्जाना लगाया

जयपुर (कासं)। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-3 ने पीएम आवास योजना के तहत लिए होम लोन को सब्सिडी के लिए दस्तावेज देरी से भेजने के चलते लाभ से वंचित रहने को सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 11 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं सब्सिडी राशि

2.67 लाख रुपए परिशद पेश करने की तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर और सदस्य पवन कुमार ने यह आदेश बिंदु चौधरी व अन्य को और से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए।परिवाद में

■ **पीएम आवास योजना की सब्सिडी के लिए दस्तावेज देरी से भेजने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कार्रवाई की**

अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार शर्मा ने आयोग को बताया कि परिवादी ने विपक्षी बैंक से करीब पांच साल पहले होम लोन लिया था और पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। विपक्षी ने परिवादी को आश्चर्य बताया था कि

करतारपुरा में रेलवे की अवैध लॉन्ड्री के खिलाफ स्थानीय लोगों का आक्रोश फूटा

जयपुर (कासं)। उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर नगर निगम के करतारपुरा क्षेत्र, वार्ड सं. 144 में रेलवे लाइन के किनारे व सरकारी स्कूल के सामने रिहायशी कॉलोनी में अवैध बूट लॉन्ड्री की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, जिनसे स्थानीय जनता विशेषकर बुढ़ों, महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य एवं श्वास संबंधी काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

रिहायशी इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बगैर भू-रूपांतरण करायेबूट लॉन्ड्री की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। ये लॉन्ड्री रिहायशी इलाके में होने पर भी नियमविरुद्ध प्रतिदिन निरन्तर 24 घंटे चालती हैं। इसकी चिमनी से आसपास की कॉलोनियों में रोजाना काफी जहरीला धुआं, मशीनों से रसायनयुक्त पानी और वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलता है। इससे स्थानीय निवासी अत्यधिक परेशान है। इस बूट लॉन्ड्री के बिबकुल सामने महज 15 मीटर की दूरी पर ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करतारपुरा स्थित है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे रोजाना प्रदूषित वायु एवं फैक्ट्री के शोर से काफी परेशान हैं एवं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि लॉन्ड्री में अवैध रूप से बॉयलर भी लगा रखा है जो कि नियमानुसार आवासीय क्षेत्र में नहीं लग सकता है। अब नई 2 युनिटों में भी अवैध रूप से 2 बॉयलर स्थापित किये गये हैं। लॉन्ड्री की फैक्ट्रियों में नियमानुसार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान आवश्यक है, लेकिन इस लॉन्ड्री में शुरूआत से ही केवल ढांचा बना हुआ है। इसको संचालित नहीं किया जा रहा है।

फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रात के समय झगड़ा फसाद करके शोर, अराजकता का माहौल बनाए रखते हैं जिससे स्थानीय निवासियों में तनाव बना रहता है। इस अवैध लॉन्ड्री से परेशान स्थानीय निवासी कई वर्षों से केन्द्र सरकार, रेलवे, प्रदूषण बोर्ड, मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार को शिकायत कर रहे हैं, परन्तु अभी तक किसी के द्वारा भी कार्यवाही नहीं की गई।

ट्रीटमेंट प्लांट सुचारू नहीं होने से रसायनयुक्त गन्दा पानी करतारपुरा नाले (ड्रव्यवती नदी की सहायक) में डालकर जल प्रदूषण भी किया जा रहा है। लॉन्ड्री की नई 2 युनिटों में तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ढांचा भी नहीं बनाया गया है, इसके बावजूद फैक्ट्री एवं बॉयलर बिभाग इनको बॉयलर लगाने के लिए अनापत्ति दे रहा है।

जयपुर के मास्टर प्लान में अभी भी इस लॉन्ड्री की भूमि को रिहायशी ही दिखाया जा रहा है। लेकिन फिर भी जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा फैक्ट्रियों के लिए अवैध रूप से नियमों के परे जाकर मिलीभगत से अवैध लॉन्ड्री को व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल को कई वर्षों से लॉन्ड्री की फैक्ट्रियों के प्रदूषण से परेशान स्थानीय निवासी शिकायत कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा भी महज कागजी खानापूर्ति करके कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस फैक्ट्री के कारण दुर्गापुरा से बाईस गोदाम जाने वाली मुख्य सड़क पर आए दिन जाम लगते रहते हैं।

फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रात के समय झगड़ा फसाद करके शोर, अराजकता का माहौल बनाए रखते हैं जिससे स्थानीय निवासियों में तनाव बना रहता है। इस अवैध लॉन्ड्री से परेशान स्थानीय निवासी कई वर्षों से केन्द्र सरकार, रेलवे, प्रदूषण बोर्ड, मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार को शिकायत कर रहे हैं, परन्तु अभी तक किसी के द्वारा भी कार्यवाही नहीं की गई।

मुकेश मीणा चौथी बार प्रेस क्लब के अध्यक्ष निर्वाचित

जयपुर । पिकसिटी प्रेस क्लब प्रबन्ध कार्यकारिणी 2026-27 के लिए मुकेश मीणा अध्यक्ष और राजकुमार शर्मा “जकडी” महासचिव निर्वाचित हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल शेखावत ने बताया कि अध्यक्ष पद पर मुकेश मीणा को 369, रोहित कुमार सोनी को 317, रूपेश टिंकर को 194 और अभय जोशी को 127 मत मिले हैं। महासचिव पद पर राजकुमार शर्मा जकडी को 430, रामेन्द्र सोलंकी को 392, परमेश्वर प्रसाद शर्मा को 112 एवं अभय सिंह को 42 मत मिले हैं।

उपाध्यक्ष के दो पदों पर डॉ. मोनिका शर्मा और पुष्पेन्द्र सिंह राजावत निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इस पद



पर डॉ. मोनिका शर्मा को 416 और पुष्पेंद्र सिंह राजावत को 399 मत मिले हैं। उन्होंने बताया कि कोषाध्यक्ष पद पर नमोनारायण अवस्थी ने 447 मत प्राप्त कर सफलता हासिल की है। इस

पद पर अनिल त्रिवेदी को 365, और शालिनी श्रीवास्तव को 166 मत मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शेखावत ने बताया कि कार्यकारिणी के दस पदों पर अनिता शर्मा आदि।